The Committee also recommended that the sitting of the Rajya Sabha fixed for Monday, the 28th of July, 2014, may be cancelled. Accordingly, there will be no sitting of the House on that day.

THE BUDGET (GENERAL), 2014-15,

AND

THE APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 2014

THE APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2014 – *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Biswajit Daimary, kindly take only five minutes.

श्री बिश्वजीत दैमारी (असम) : सर, इस बजट पर बोलते समय यहां के जाने-माने सदस्यगण ने इस देश के बारे में, राज्यों के बारे में और शहरों के बारे में चर्चाएं की हैं। मैं भी सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट की तरफ या उत्तर पूर्वी क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारा नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही बैकवर्ड है, यह सब लोग जानते हैं। इस बजट में नॉर्थ-ईस्ट के लिए जितने फंड का प्रोविज़न रखा गया है, वह सफिशिएंट नहीं है। जितने भी मंत्रालय हैं, जिनमें सारे देश के लिए जितने फंड का प्रोविजन रखा गया है, मुझे संदेह है कि उसमें नॉर्थ-ईस्ट के लिए भी होगा। क्योंकि जब भी देश के लिए बजट बनाया जाता है तब नॉर्थ-ईस्ट के लिए कुछ न कुछ कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह नॉर्थ-ईस्ट को कभी नहीं मिलता है। नॉर्थ-ईस्ट के लिए डबल फंड का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट पहाड़ी इलाका है। असम, जिसको प्लेन राज्य कहा जाता है, वह भी बहुत सारे पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। असम के बीच में भी बहुत सारे जिले, पहाड़ी इलाके वाले हैं, जिनको डेवलप करने के लिए बहुत फंड की जरूरत है। उसके प्लेन एरिया होने के बावजूद वहां नेशनल हाइवे या रोड बनाने के लिए जो 3000 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा गया है, वह उन पहाड़ी इलाकों में रास्ता बनाने के लिए कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकता है। असम, जो कि प्लेन एरिया है, अगर वहां रास्ता बनाना पड़े तो दो-दो किलोमीटर पर एक ब्रिज बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि वहां बहुत सारी नदियां हैं। तो इसके लिए जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों के लिए विचार किया जाता है, परियोजनाएं ली जाती हैं तो सेम मॉडल में, सेम स्टाइल में नॉर्थ-ईस्ट में ऐसी परियोजनाओं पर कभी कार्य नहीं किया जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। सर, जो विभिन्नि मंत्रालय हैं उनके जरिए भारतवर्ष के बहुत राज्यों में कुछ-कुछ करने के लिए यहां पर मेंशन किया गया है, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे, IIT, IIM, AIIMS हर राज्य में खोलने की बात थी, लेकिन सिर्फ 5 राज्यों के लिए घोषणा की गई है। अगर इसमें से नॉर्थ-ईस्ट के किसी भी एक राज्य को शामिल किया जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट बहुत पिछड़ा हुआ है। जिस तरह देश की बाकी जगहों के लिए, एक्स्ट्रीमिस्ट एरियाज के लिए वहां के डेवलपमेंट के लिए चिंता की गई है, उसी तरह नॉर्थ-ईस्ट के एक्स्ट्रीमिस्ट धारा में शामिल हिस्सों के डेवलपमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज वहां पर कोई भी काम क्यों न करें, सरकार जितना खर्चा करेगी

उसके समान एक्स्ट्रीमिस्ट, उग्रवादी भी लेकर जाता है। जिस तरह हमारे डिफेंस के लिए और हमारे मिलिट्री फोर्स के लिए, पुलिस के लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन की जरूरत होती है, इसी तरह नॉर्थ-ईस्ट को उग्रवादी भी आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदता है और इसके लिए सारा पैसा जो हमारे डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है, वहीं से वे लोग एक्सटॉर्शन करते हैं। तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट्स में डबल पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर वहां एक्सट्रीमिस्ट्स को पैसा मिलेगा, तभी वहां कांट्रेक्टर वगैरह काम कर सकेगा और तभी वहां टेक्नीकल पर्सन साइट पर जा सकेगा। यह सही बात है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी प्राजेक्ट सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म सर्किट बनाने की बात कहीं गई है। नॉर्थ-ईस्ट में भी इस तरह के बहुत सारे मौके हैं। वहां पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चाहें तो नॉर्थ-ईस्ट में भी टूरिस्ट सर्किट बन सकता है। कुछ जगहों की पब्लिसिटी करके वहां पर टूरिस्टों को लाने की व्यवस्था की जा सकतीहै। अगर हाऊस एग्री करता है तो आज वहां जो उग्रवादियों का डेजिनेटेड कैम्प हैं, उसको भी टूरिज्म के मैप में लाया जा सकता है। 50 से भी ज्यादा उग्रपंथी - एक्सट्रीमिस्ट्स वहां सीजफायर में हैं। वहां जाकर उन लोगों के साथ टूरिस्ट खा-पी सकता है। इस तरह से कोई भी टूरिस्ट उन लोगों के साथ बैठकर इस तरह से बातकर सकता है कि उन्होंने किस कारण से आर्म्स पकड़ा, क्यों उनके हाथ में बंदूक है, बारूद है, क्योंकि खुलेआम टूरिस्टम ही उनके डेजीनेटेड कैम्प में उनके साथ बैठकर बात कर सकता है। तो हम उसको भी टूरिज्म के सैक्टर में क्यों नहीं ला सकते, जो कि बाकी देश में नहीं कर सकते, जिसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे दी है। आज वहां पर बाढ़ है,फ्लड है, उसको भी टूरिज्म में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली में बारिश नहीं होती है, यू.पी. में बारिश नहीं होती है। अगर वे लोग असम में जाएंगे तो कम से कम बाढ़ देखने को मिलेगी। इसके लिए भी तो टूरिज्म हो सकता है। इसी तरह कुछ न कुछ वहां पर किया जा सकता है। ...(**समय की घंटी**)... असगोंडा के लिए वह चाहे कंजर्वेशन के लिए हो, चाहे जो भी हो उसके लिए इतना सारे रुपए का प्रोविजन रखा है। हम लोग जानते हैं कि असम में जो माजुली है, जो विश्व के नदीद्वीप से प्रसिद्ध है और जहां पर सदियों से वहां के लोग भारतीय कला संस्कृति और धार्मिक रीति-रिवाज को अपनाकर जीवन-निर्वाह कर रहे हैं, उन लोगों को बसाने के लिए माजुली को बसाने के लिए इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। मैं थोड़ा सा बोडोलैंड के बारे में और बोलना चाहता हूं। असम का जो बोडोलैंड इलाका है भूटान के सामने, वहां पर एजुकेशनल सैक्टर में बहुत काम करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो IIT, IIM, AIIMS बनाने की याजना है, वहां पर भी ऐसी व्यवस्था करें।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री वी.पी. सिंह बदनौर**) *पीठासीन हुए*]

वहां पर ड्रिंकिंग वॉटर का बहुत क्राइसेज है। पहाड़ के सामने होने के कारण खुदाई करके वहां पर कोई कुआं वगैरह नहीं बना सकता है, ट्यूववैल नहीं लगा सकता है। इस बारिश के समय में भी नॉर्थ-ईस्ट से पानी बह रहा है लेकिन जमीन के अंदर से पानी नहीं निकल रहा है। वहां के लोग 10-50 किलोमीटर दूर से पानी लाकर पी रहे हैं। तो वहां के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमारी जो काउंसिल है, वह इंडियन कांस्टीट्यूशन के सिक्सथ शेड्यूल के आधार पर है। वहां पर स्टेट की तरह सारे डिपार्टमेंट को संभालने के लिए क्षमता दी गई, लेकिन हमारे केन्द्रीय सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं इनके काम करने के लिए जो गाइडलाइंस

[श्री बिश्वजीत दैमारी]

बनाई गई हैं.... वे सिक्स्थ शेड्यूल के अनुसार इस बारे में कैसे कार्यवाही करेंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी कारण असम का जो सिक्स्थ शेड्यूल्ड एरिया है Karbi Anglong, एन.सी. हिल्स और बोडोलैंड - उसमें एन.आर.एच.एम., जोकि स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और हर मंत्रालय ने इसे लिया है, वहां पर एन.आर.एच.एम. का कार्य नहीं चल रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का काम नहीं चल रहा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का काम नहीं चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना का काम भी नहीं चल रहा है। इस कारण जब प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर के द्वारा काम कराया जाता है, लेकिन बोडोलैंड में डी.सी. का वहां पर कोई काम नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE) : Thank you.

श्री बिश्वजीत दैमारी : ऐसी गाइडलाइंस के कारण वहां पर जो अचानक प्राकृतिक आपदा आती है या समस्या पैदा होती है, वहां के लोगों को इस आपदा के समय कोई सहायता नहीं मिलती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इन सारी चीजों को देखकर इसके लिए मैकेनिज्म निकालें, गाइडलाइंस को चेंज करें। उसमें सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन करें कि वहां के मंत्रालय सेंटर के इस प्रोग्राम को किस तरह से कार्यान्वित करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE) : Thank you very much.

श्री बिश्वजीत दैमारी : महोदय, मैं अंत में अनुरोध करूंगा कि कम-से-कम डोनर के लिए जो पैसा रखा गया है और नॉर्थ-ईस्ट के लिए और मंत्रालयों से जो नॉन-लैप्सिबल फंड में दिया गया है, उसी की तरह से वहां की स्थिति को बदलने के लिए कम-से-कम 1 हजार करोड़ रुपए आप यहां से ईयरमार्क करके भेजें ताकि बोडोलैंड की स्पैसिली इन तमाम समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कदम उठा सकें। इतना की कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Thank you, Sir. I express my gratitude for giving me the opportunity to participate in the ongoing discussion on the General Budget proposals. Many senior parliamentarians, including veterans from my party, have talked in detail on diverse proposals contained in the Budget speech. I do not consider myself qualified enough or equipped to speak on the complexities of the Union Budget. But, I would venture to put forth my views that reflect common man's reaction to the impact of the Budget proposals.

Sir, hailing from the North-East, I will confine myself on as to how Budget proposals affect the people of the North-East. Sir, the North-East Region is lagging behind on development aspects in comparison to other parts of the country. The Region is connected with the mainland nation by an umbilical cord-like link, we call it, chicken neck a fourteen-kilometre wide and hundred-mile long corridor, flanked by Nepal in the North and Bangladesh in the South. This Union Budget has no major initiative of

Government for the North-East, either with regard to infrastructure development or on emphasizing economic development of the Region.

Sir, the UPA Government, for the last ten years, have been constrained in taking up several initiatives to address the issues of the North-East. Here, a dedicated funding provision, namely, North East Special Accelerated Road Development Programme (NE-SARDP) has been made for the development of all sorts of road, either the State road or the National Highway. And, for the last three years, an amount of Rs. 8,750 crores has been sanctioned and released in the SARDP-NE. But, in this year's Budget, there is no mention about the SARDP-NE, which gives boost to the development of road communication in the region. Sir, work progress of East-West Corridor Project in the North-East is progressing. Out of 670 kilometre length of this project in North-East, till date, 30 to 35 per cent of road length has been completed. Construction work on the remaining part of East-West Corridor is still pending. Even, the construction work of a bridge over Brahmaputra near Saraighat is still going on. There was a proposal by the UPA Government of connecting all State Capitals of North-East with East-West Corridor with four-lane highways. But, this Budget is completely silent upon Government's previous move over completing the pending work of the East-West Corridor of North-East part. Sir, the UPA Government always stressed on the upliftment of the North-East and in 2008 had released the North-Eastern Region Vision 2020 Document, which sets the goals, identifies the challenges and suggests regional and sectoral implementation strategies for promoting socio-economic prosperity in the region with a view to bringing growth rate in the North-East Region on a par with the overall national growth rate. The document suggests a six-fold strategy for the comprehensive development of the region by creating development opportunities for the rural areas through enhancing productivity in agriculture and allied activities such as animal husbandry, horticulture, floriculture, fisheries and generation of livelihood options through rural non-farm employment. Hence, I urge upon the Government and hon. Finance Minister to revisit North East Vision Document 2020 and take effective measures to implement its recommendations.

Sir, we must recall that our new Prime Minister Narendra Modiji has shown his concern and commitment for the North-East during election campaign. In his speech on the floor of the Lok Sabha, he mentioned his Government's thrust on emerging North-East region as organic State, which would be a better example for the country as well as the world and will greatly contribute towards the upliftment or economic development of the region. It really needs to be so because the North-East has been blessed with natural and human resources that can greatly contribute to the overall development of this region as well as the country.

[Shrimati Wansuk Syiem]

But I must express that in this Budget the commitment in terms of strategies or specific policies to elaborate the process of enhancing North-East as an organic region is not reflected.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): How long will you speak?

SHRIMATI WANSUK SYIEM: Sir, this is my maiden speech.

The UPA Government striven to attract optimum investments from the South Asian countries as well as neighbouring countries, for the North- Eastern Region through initiatives under the Look East Policy. The Policy was perceived in a multi-faceted manner, in diverse areas such as improved connectivity, promotion of trade and investment and cultural exchanges with South East Asian countries. The North-Eastern Region would be a trade corridor. Within the purview of the Look East Policy in some sectors like tourism, energy, agriculture, transportation and communications along with public health and people-to-people contact, the North East must play a vital role with more viable prospects that would help the region in sustainable development.

Sir, I should not miss the positive aspect of the new proposal which Government has mooted to promote inter-border trade within local communities across Bangladesh-Meghalaya border.

Sir, I request the Government and the Finance Minister to continue with all these projects. I hope it will strive towards transforming the North-Eastern Region and its people as an integral part of the nation and truly Indians. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V.P. SINGH BADNORE): Shri Ram Kumar Kashyap, you have got only four minutes.

SHRI RAM KUMAR KASHYAP (Haryana): Sir, it is my maiden speech. उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका सिर झुका कर धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी का यह पहला बजट है और इस बजट पर मेरी यह मेडन स्पीच है। मैं हरियाणा का निवासी हूं और एक आम परिवार से संबंध रखता हूं। मैंने आपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि मैं भी कभी हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्य सभा का सदस्य बनूंगा और आप मुझे वित्त मंत्री जी के पहले बजट पर बोलने का मौका देंगे। आपने मुझे मोका दिया, इसके लिए मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं अपनी पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राज्य सभा सदस्य नामित किया है।

वित्त मंत्री महोदय, आपने हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए एक संतुलित बजट पेश

किया है, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। वित्त मंत्री महोदय, इस बजट में आपने वनों के विकास के लिए और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए 1,169 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पैसे का, इस मद पर, सही इस्तेमाल करने से वन्य प्राणियों की रक्षा होगी तथा वनों का विकास भी होगा। वनों का विकास होने पर हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा और हमारे अनुकूल होगा। वनों के विकास से वर्षा में बढ़ोतरी होगी। महोदय, एक समय ऐसा था, जब हिन्दुस्तान में वर्षा की स्थिति बहुत अच्छी होती थी। मैंने अपने जीवन में लगातार पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक वर्षा होते हुए देखा है। इतनी वर्षा होती थी कि मकानों की छतों पर भी इस प्रकार का खरपतवार उग जाती थी, जैसे कि हमनें छतों पर खरपतवार की बिजाई की हो, परंतु अब तो हमें अपने मकानों की छतों पर इस प्रकार की कोई वनस्पति उगती नजर नहीं आती, क्योंकि अब वर्षा उतनी नहीं होती, जितनी साठ के दशक में होती थी। उस समय जंगल बहुत होते थे। हर जगह पेड़-पौधे उगे हुए नजर आते थे। हर जगह हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। इस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई और वह भी लेट हुई, जिसके कारण समस्त भारत में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई। पिछले दिनों सूखे की समस्या पर सदन में चर्चा हुई और समस्त सदन ने इस पर अपनी गहन चिंता भी जाहिए की है। वर्षा न होने का मुख्य कारण यह है कि हमने अपनी सुख-सुविधाओं के लिए अपने जंगलों को काटने की भारी मात्रा में किया। साथ ही, हमने अपने खेतों से और अपने घरों से भी वृक्षों को, पेड़ों को काटने का काम किया। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और अब प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। इंग्लिश में एक proverb है-

"To whom evil is done, do evil in return."

प्रकृति का हम नुकसान करेंगे तो naturally प्रकृति भी हमारा नुकसान करेगी। भविष्य में अच्छी वर्षा हो और सूखे जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, मंत्री महोदय, इसके लिए हमें जलों के विकास पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वृक्षों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाना होगा। उनको लगाना ही नहीं होगा, बल्कि उनकी देखभाल करनी होगी, उनकी मेन्टेन करना होगा। वृक्षों को लगाने व उनकी देखभाल करने में भारत का हरेक नागरिक अपना अहम योगदान दे सकता है। इस पर मंत्री महोदय को मेरा एक सुझाव है कि पेड़ों के विकास के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए, जिसके अंतर्गत हरेक नागरिक के लिए एक पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया जाए और हरेक नागरिक, चाहे वह अपने घर में, चाहे अपने खेतों में, चाहे सरकारी पार्कों में या सड़क के किनारे पर एक पेड़ लगाने का काम अवश्य करेगा। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उसको सरकारी सुविधा तब तक न दी जाए, जब तक कि वह लिखकर यह सुनिश्चित न करे कि उसने पेड़ लगाने का काम किया है। जब ऐसा काम होगा, तो निश्चित तौर से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे हिन्दुस्तान का हर गांव और हर शहर हरा ही हरा नजर आएगा। कुछ दिनों के बाद हरियाली नजर आएगी।

मंत्री महोदय, आपने बजट में अनुसूचित जातियों व अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को, शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए 2,285 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मंत्री महोदय, यह आपका एक स्वागत योग्य कदम है। इस राशि में से 1,500 करोड़ रुपए एस.सी. छात्रों को और 785 करोड़ रुपए की राशि अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने में खर्च

[Shri Ram Kumar Kashyap]

होगी। मंत्री महोदय, ओ.बी.सी. के छात्रों की जनसंख्या को अगर देखें, तो यह राशि बहुत कम पड़ती है, इसलिए मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस राशि को कम से कम दोगुना करेंगे, तो मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करूंगा।

मंत्री महोदय, शिक्षा से संबंधित एक अन्य मुद्दे पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं और हरियाणा में ओ.बी.सी. की जनसंख्या लगभग 41 परसेंट है। ओ.बी.सी. वर्ग में बंजारा, पाल गडरिया समाज, धोबी, नाई, लोहार, बढ़ई कश्यप राजपूत जैसी जातियों की आर्थिक स्थिति तो इतनी खस्ता है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलाने में आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं। ...(**समय की घंटी**)... कई बार तो ऐसे विद्यार्थियों को फीस, दाखिला, किताबों व होस्टल का खर्चा वहन न कर पाने के कारण स्कूल और कॉलेज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। पिछले दिनों हरियाणा के जिला करनाल में एक ऐसा मामला मेरे नोटिस में आया कि पाल गडरिया समाज का एक छात्र एम.बी.बी.एस. की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। अंतिम वर्ष की पढ़ाई के लिए उसे दो लाख रुपए की राशि की जरूरत थी लेकिन वह राशि उसके मां-बाप देने में असमर्थ थे। उनकी असमर्थता के कारण वह छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गया है। मंत्री महोदय, मुझे भी विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं 1976 में एल.एल.बी. में दाखिला लेना चाहता था। मेरा लिस्ट में नम्बर आ गया था, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे की तंगी थी, मैं समय पर पैसे का प्रबंध नहीं कर सकता। पैसे की तंगी के कारण मेरा वह साल खराब हो गया, मैं दाखिला नहीं ले सका। मैंने अगले साल पैसे का अरेंजमेंट किया और अपनी लॉ की पढ़ाई की। मंत्री महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में ऐसा बहुत से छात्र हैं जिनकी स्थिति इसी प्रकार की है, मैंने तो केवल दो ऐसे उदाहरण दिए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप, ऐसे गरीब बच्चों के लिए, जो पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं, हिन्दुस्तान के लेवल पर एक ऐसे कोष का गठन करने का काम करें, जिस कोष से वे बच्चे इंटरस्ट फ्री लोन लेकर अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें और एक अच्छे नागरिक बन कर हिन्दुस्तान के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। मंत्री महोदय, मैं हरियाणा को बिलॉग करता हूं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री वी.पी. सिंह बदनौर**) : आप चेयर को एड्रेस करें।,

श्री राम कुमार कश्यप : सर, एक मिनट। मेरी हरियाणा के संबंध में एक मांग है। मंत्री महोदय, आपने हरियाणा के लिए बागवानी विश्वविद्यालय देने का काम किया है...

उपसभाध्यक्ष (**श्री वी.पी. सिंह बदनौर**) : आप मंत्री महोदय को एड्रेस न करें, चेयर को एड्रेस करें।

श्री राम कुमार कश्यप : उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री देने का काम करें। ताकि युवाओं को उससे रोजगार मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

डा. संजय सिंह (असम) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। मैं वित्त मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन

करता हूं कि उन्हें पहला बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मुझे आशा है कि देश के करोड़ो लोगों के 'अच्छे दिन' की कल्पनाओं को साकार करने का उन्हें अवसर मिलेगा। माननीय महोदय, यह बजट कई मामलों में ऐतिहासिक बन जाता है। पहली बात तो यह है कि 29 साल के बाद यह सरकार बहुमत की सरकार है और इसका नेतृत्व हमारे ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। सर, इस बहुमत की सरकार से लोगों को बहुत आशाएं थीं, 'अच्छे दिन' और 'गुड गवर्नेंस, लैस गवर्नमेंट' के बहुत नारे चुनाव में लगे थे। हमें लगता है कि इस बजट ने उन नारों की हवा निकाल दी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मिनिमम गवर्नमेंट की यह कैसी व्यवस्था है कि लगभग हर चीज में सौ करोड़ का प्रावधान है, लेकिन ऐसी बड़ी-बड़ी समितियां बनी हैं, जिनमें वे ये तमाम चीजें गवर्न करना चाहते हैं। माननीय महोदय, अच्छे दिन की उम्मीद वाली इस सरकार के आने पर बहुत सारे लोगों के अरमान टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह भी एक ऐतिहासिक बात बनेगी। महोदय, इससे पूर्व, 29 साल पहले माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भी बहुमत की सरकार आयी थी। उस समय आई.टी. सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में यह देश महाशक्ति बना था। आज यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि चाहे वह गुड़गांव हो, हैदराबाद हो या बैंगलुरू हो, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां बहुत कोशिश करके इन स्थानों पर अपने दफ्तर खोल रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि यहां पर उन्हें स्थान मिले। इसी बदलाव में 1985 की सरकार ने साहसिक योजनाओं और तमाम स्कीमों से अपने देश को महाशक्ति बनाया था। उस समय सीडैक और सीडॉट जैसी संस्थाओं को स्थापित करके हमारे इस कृषि प्रधान देश को उस सेक्टर में बहुत बड़ी क्षमता दिखाने का यह परिणाम हमें मिला था। हमें लगता था कि यह सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में संपूर्ण देश को उस दिशा में ऐसा मार्गदर्शन देगी, ऐसा मौका देगी कि जो आम आदमी है, वह अपने लिए कुछ कर सकेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको पछतावा हो रहा है और लोग चर्चा करके यही पूछ रहे हैं कि वे अच्छे दिन कब आने वाले हैं? माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बहुमत की सरकार देश की दशा को ऐसी दिशा देगी, जिससे लोगों में कांफिडेंस और भरोसा पैदा होगा?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि किसी भी बजट के लिए पैंतालीस दिन बहुत कम होते हैं। मैं मानता हूं कि यह बात सही है, लेकिन माननीय मंत्री जी को हमारी यह बात माननी पड़ेगी कि एक अच्छी दिशा का अहसास कम से कम पैंतालीस दिनों में दिलाया ही जा सकता था। मैं यह समझता हूं कि जो करोड़ों लोग अच्छे दिनों के इंजतार में, मतदान देकर इस बहुमत वाली सरकार को लाए थे, उन लोगों को इस पर बहुत पछतावा है और वे चर्चा कर रहे हैं कि वे अच्छे दिन कब आएंगे।

माननीय महोदय, मैं दो मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आवास व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं कि दस सालों में हर मकान की कीमत दस गुना बढ़ गई है। आज अगर आम आदमी का एक करोड़ रुपये का मकान खरीदना चाहे, तो उसको उस पर 1000 रुपये की छूट मिल रही है। मुझे नहीं लगता है कि यह छूट उसके लिए कोई खास राहत है। आज रियल एस्टेट की कंपनियां बनिस्पत आई.टी. सेक्टर की कंपनियों से ज्यादा लाभ कमा रही हैं। मुझे लगता है कि इस बजट में कंस्ट्रक्शन की लाइन वाले लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। जो मकान खरीदने वाले लोग हैं, उनके लिए बजट में कोई खास राहत की बात नहीं की गई है।

[डा. संजय सिंह]

महोदय, स्वास्थ्य के बारे में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि देश में दस एम्स और खुलेंगे। मुझे लगता है कि एम्स खोलने की जगह, देश की जनसंख्या के हिसाब से अगर कम से कम दस जिलों पर एम्स खुलें और उनकी गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दें, तो उस तरफ ज्यादा डायरेक्शन मिलेगी।

भारत सरकार प्रदेशों को भी हजारों करोड़ रुपये आवंटित करती है, लेकिन जिस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग होता है, उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी उस तरफ ध्यान देंगे कि उन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, वहां के डॉक्टर्स पर ध्यान और तमाम पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसको कैसे रोकें। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डॉक्टरों ने जेलों में स्युसाइड किया था उनकी सी.बी.आई. जांच चली थी। हमें इस तरह की तमाम घटनाएं सुनने को मिलती हैं।

***(उपसभापति महोदय** पीठासीन हुए)*

माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान नॉर्थ-ईस्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। नॉर्थ-ईस्ट देश की जनसंख्या के औसत से केवल 8 प्रतिशत है। यदि आतंकवादी गतिविधियों को लें, तो वहां पर देश की 70 प्रतिशत घटनाएं घटित हो रही हैं। इसका भी कारण है। कारण यह है कि वहां पर नौजवानों के लिए रोजगार नहीं हैं। वहां पर तमाम लोगों के खेल-कूद की व्यवस्था, फल और सब्जी के कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर उस सामान को विदेशों में न भेज सकें, तो कम से कम देश के बड़े नगरों में अपने उत्पाद बेच सकें,। ...(**समय की घंटी**)... मैं आपके दो मिनट और लूंगा। असम में विकास के लिए बजट का दस प्रतिशत एलोकेट होता है। वहां पर तमाम ऐसे रोजगार दिलाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापना की कोशिशें अवश्य हो रही हैं, सबसे बड़ी समस्या जो, वहां दिखाई देती है, वह बाढ़ की है। इसकी वजह से असम में विकास का कोई काम होता दिखाई नहीं देता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री जी से आश्वासन भी चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था हो कि इसका कोई परमानेन्ट हल निकल सके। वहां पर बहुत रीनोज़ मारे जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि वह स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इस देश में राष्ट्रीय महत्व के जो ऐसे पशु हैं, वन्य जीव हैं ...(**समय की घंटी**)... मैं चाहता हूं कि उनको सुरक्षा देने की व्यवस्था केन्द्र से सुनिश्चित हो। महोदय, मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस देश के बजट में आम आदमी और किसानों के लिए कुछ अच्छा सोचा जाए। देश में एक सुई बनाने का वाला व्यक्ति भी उसका दाम निश्चित कर सकता है, लेकिन किसान, जो जाड़े, गर्मी और बरसात में मेहनत करके देश ही नहीं, बल्कि दुनियां के कई देशों को अपने उत्पाद से अनाज भेजता है, उसके बारे में नहीं सोचा जाता है। लेकिन किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ...(**समय की घंटी**)... इसलिए इसके बारे में भी ध्यान दिया जाए।

आज असम और नॉर्थ-ईस्ट के जितने राज्य हैं, वे इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि उनके लिए एक विशेष पैकेज या विशेष व्यवस्था हो, जिससे वे इस देश की मुख्यधारा से हर समय जुड़े रहें और...(**समय की घंटी**)... ऐसा न लगे कि जैसे हमारे देहात में नहर में पानी नहीं पहुंचता, वैसा हो। नॉर्थ-ईस्ट में भी दिल्ली की सत्ता का प्रताप पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था हो। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now I just want to know one thing. There are five or six names which are not there in the list. These Members have given their names

now and they are insisting and pressurizing me. If the House agrees, I will give two minutes to each of them. ...*(Interruptions)*... Okay, three minutes. After three minutes, the mike will be switched off and .the rest of the speech will not be recorded. On that condition, I can call. But I will tell you that I am allowing this because it is a discussion on the Budget. Otherwise, I would not have allowed it. But, hereafter, make it a point to give your names in advance and 'Others' also, who speak, should speak within the time allotted to them. If everybody is taking more time, then, what can the Chair do?

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : सर, 30 तारीख को फाइनेंस बिल आएगा, तो इन लोगों को उसमें बोलने का मौका दे दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a good suggestion. They can give their names for that discussion. I would read out their names, and they can give their names in advance for the discussion on the Finance Bill.

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI: We have other names for the Finance Bill and this must be the case with other parties as well. So, the Budget speakers should speak on the Budget. Whatever time-limit you have set, that is okay.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, I agree. I will give just three minutes and, after that, the mike will be switched off. Now, Shri G.N. Ratanpuri. Not present. Shri Ramdas Athawale.

(महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, हमारे एन.डी.ए. के वित्त मंत्री, अरुण जेटली जी ने 2014-15 का जो बजट पेश किया है, उस बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस साल का जो बजट है, अभी उनको सिर्फ 40-45 दिन ही मिले हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि बजट में यह नहीं है, वही नहीं है, पैसा कहां से लाएंगे? कहां से पैसा लाना है, इसके लिए हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता है। अभी तो ये कह रहे हैं कि यह बजट ऐसा है, यह बजट वैसा है। आपका बजट कैसा था? अभी हमें काम तो करने दीजिए। अभी नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, हमारी सरकार अभी आई है, हमें थोड़ा प्लान करने दीजिए। अगर हम टैक्स बढ़ाते, तो ये कहते कि यह बढ़ाया, वह बढ़ाया। रेलवे में हमने ट्रायल किया कि रेलवे में थोड़ा भाड़ा बढ़ाने से इनका क्या रिएक्शन आता है, तो ये एकदम हंगामा करने लगे। इसलिए अरुण जेटली जी जो बजट लाए हैं, उस बजट के आने के बाद एक भी आन्दोलन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि यह बजट अच्छा है। लोग यह कह रहे हैं कि इनको कुछ देने चाहिए। इनको 50-60 साल मिले, अगर हमको कुछ दिन भी नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे? इसलिए अभी मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि-

'अरुण जेटली जी का बजट है अच्छा,
इसलिए खुश है देश का बच्चा-बच्चा।
अरुण जी, आपको मौका मिला है, अब तो आप काम करो सच्चा,

[श्री रामदास अठावले]

और मैं करता हूं काग्रेस का पिच्चा।
हम तो सत्ता में रहेंगे कम-से-कम दस साल,
देखते रहेंगे हम कांग्रेस का क्या होता है हाल।
इन लोगों ने बहुत कमाया है माल,
महंगी करके दाल।
नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे कम-से-कम दस साल,
उनका कोई नहीं करेगा बांका बाल,
क्योंकि हमने खड़ी की है बहुत मजबूत वॉल।'

श्री उपसभापति : अब आपके तीन मिनट हो गए। ...(**व्यवधान**)...

The mike is off. Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... आपके तीन मिनट हो गए, now, Shri Arvind Kumar Singh. ...*(Interruptions)*... Athawaleji, it is not going on record.

अठावले जी, आप बैठ जाइए, यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। अरविन्द जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावले : *

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) : सर, कैसे बोलें? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपका रिकॉर्ड में जा रहा है, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

Shri Athawale, please sit down. ...*(Interruptions)*... This is very bad. ...*(Interruptions)*... You sit down. ...*(Interruptions)*... What are you doing? ...*(Interruptions)*... This is very bad on your part. ...*(Interruptions)*... I gave you time. Don't do this. ...*(Interruptions)*... What is this? Don't do this, please. ...*(Interruptions)*... आप बात को समझते नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... This is indiscipline.

श्री रामदास अठावले : *

श्री अरविन्द कुमार सिंह : माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मेरी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नारा है 'कपड़ा-रोटी सस्ती होगी, दवाई पढ़ाई मुफ्त होगी'। महोदय, जिस तरह से कुदरत से हमें धूप मुफ्त में मिलती है, हवा मुफ्त में मिलती है, पानी मुफ्त में मिलता है, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में जाने वाला ज्ञान भी हमें मुफ्त में मिलना चाहिए।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब छात्रों को कुछ देने की बात आई, तो वे झपकी लेने लगे। प्रतिभा दौलत की मोहताज नहीं होती है। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज मेडिकल और

*Not recorded.

इंजीनिरिंग की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। गरीब का बच्चा टैस्ट पास कर लेता है, लेकिन महंगी शिक्षा होने की वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पाता है। हालांकि एजुकेशन लोन की व्यवस्था है, लेकिन मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि एजुकेशन लोन ब्याजमुक्त होना चाहिए। यदि आप एजुकेशन लोन ब्याजमुक्त कर देंगे, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीब का बच्चा भी कर सकता है, इसलिए हमें एजुकेशन लोन की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा।

मुझे याद है, बनारस के हमारे एक मित्र के छोटे भाई ने मेडिकल का टैस्ट पास कर लिया था, लेकिन जब वह बैंक में लोन लेने के लिए गया, तो बैंक के अधिकारियों ने इतना दौड़ाया कि एडमिशन की तारीख ही समाप्त हो गई, लेकिन बैंक से लोन नहीं मिल पाया।

माननीय मंत्री जी, आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। छात्रों की पीड़ा क्या होती है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरा बस एक ही आग्रह है कि जो छात्र हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please sit down. Your time is over. Now you please sit down. It is not going on record. Your time is over. Now, Chaudhary Munavver Saleem. ...*(Interruptions)*... I don't want anybody's recommendation. Mr. Arvind Kumar Singh, please sit down.

श्री अरविन्द कुमार सिंह : *

चौधरी मुनव्वर सलीम : माननीय उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)... मेरी पार्टी की ओर से माननीय नरेश अग्रवाल जी बोल चुके हैं, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। आपने जो वक्त दिया है, वह बहुत है। 'इन्कलाब जिन्दाबाद' एक शब्द भी परि वर्तन के लिए बहुत होता है।

सर, यह हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी का कमजोर बजट है। बजट की खुसूसियत यह होती है कि बजट से समाज के कमजोर तबकों को क्या फायदा मिल रहा है, बजट की गुणवत्ता इस बात पर डिपेंडेंट होती है। महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट में वे किसान, जिनके लिए कभी मेरे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने नारा दिया था, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि मुल्क में आज तक नारों पर राजनीति होती रही है। एक नारा 'जय जवान जय किसान' आया। माननीय उपसभापति जी, वह नारा सिर्फ नारा ही रह गया। जवान ही हालत यह है कि जिसने पाकिस्तान के टैंक उड़ाए, उस हवलदार अब्दुल हमीद के बच्चे आज रोजगार को तरस रहे हैं। अजहरूद्दीन ने अगर एक विकेट ले लिया, तो वे डेढ़ करोड़ की लैंड क्रूज़र ले कर आ गये। जवान की हालत बुरी हुई। दूसरा नारा 'गरीबी हटाओं' आया। गरीब दुगने हो गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। तीसरा नारा 'अच्छे दिन लाओ' आया।

माननीय उपसभापति महोदय, यह किसानों का देश है। इस देश में धरती मां का सीना प्यास से फट रहा है। सूखे के दिन हैं, लेकिन खेतों की सिचाई के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं, जबकि 60 हजार करोड़ रुपये स्मार्ट शहरों के लिए दिए गए हैं। मैं इससे एक मिसाल साबित करना चाहता हूं कि यह बजट मुट्ठी भर लोगों के लिए बना है। बजट से नौजवान मायूस

*Not recorded.

[चौधरी मुनव्वर सलीम]

हुआ है और बजट से मुसलमान मायूस हुआ है। बजट से वह तबका मायूस हुआ है, जो 43 करोड़ है। मेरे ही एक सवाल के जवाब में यहां कहा गया था कि जिसकी रोज की आमदनी अब 32 रुपये आंकी जाती है, पहले यह 28 रुपये आंकी जाती थी। महोदय, मैं उन परिवारों को जानता हूं, जिनमें मेम साहब का कुत्ता 28 रुपये से ज्यादा का खाना खाता है। अगर उन 43 करोड़ लोगों को बजट ने मायूस किया है, तो मैं यह कह सकता हूं कि मेरे विद्वान भाई माननीय जेटली जी, जिनकी बुद्धिमत्ता को देश सलाम करता है, शायद उनका बजट किसी के दबाव में बना हुआ बजट है। इसलिए यथार्थ हिन्दुस्तान का गरीब नौजवान, मुसलमान उससे मायूस हुआ है, किसान मायूस हुआ है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश के बहुसंख्यकों को सामने रख कर, नारों के बजाय देश के बहुसंख्यक समुदाय को सामने रख कर, उनकी गरीबी और उनकी तकलीफ को देख कर, अपने बजट पर एक बार नजरसानी करें। मैं बजट की आलोचना से ज्यादा उन्हें मशवरा देना चाहता हूं कि यह बजट मुट्ठी भर लोगों के लिए बनाया गया बजट है। मैं जानता हूं कि मेरे पास समय नहीं है। आपने मुझे अगर एक मिनट भी दिया, तो मैं कहता हूं कि इंकलाब बरपा करने के लिए वह बहुत होता है। ...(**व्यवधान**)... मैं देश को बताना चाहता हूं कि ...(**समय की घंटी**)... ...(**व्यवधान**)...

†**चودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش)** : مانّنے اپ سبھا پتی مہودے، ...(مداخلت)...) میری پارٹی کی اور سے مانّنے نریش اگروال جی بول چکے ہیں، لیکن مجھےبھی کچھہ کہنا ہے۔ آپ نے جو وقت دیا ہے، وہ بہت ہے۔ 'انقلاب زندہ آباد' ایک شبد بھی بہت ہوتا ہے پریورتن کے لئے۔

ودوان وتّنے منتری جی کا کمزور بجٹ ہے۔ بجٹ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بجٹ سے سماج کے کمزور طبقوں کو کیا فائدہ مل رہا ہے، بجٹ کی گنوتّا اس بات پر ڈپینڈ ہوتی ہے۔ لیکن مہودے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں وہ کسان، جن کے لئے کبھی میرے نیتا ملائم سنگھہ یادو نے نعرہ دیا تھا، ملائم سنگھہ یادو جی کہتے ہیں کہ ملک میں آج تک نعروں پر راجنیتی ہوتی رہی ہے۔ ایک نعرہ 'جے جوان، جے کسان' آیا۔ مانّنے اپ سبھا پتی جی، وہ نعرہ صرف نعرہ ہی رہ گیا۔ جوان کی حالت یہ ہے کہ جس نے پاکستان کے ٹینک اڑائے، اس حولدار عبدالحمید کے بچے آج روزگار کو ترس رہےہیں۔ اظہر الدین نے اگر ایک وکٹ لے لیا، تو ڈیڑھہ کروڑ کی لینڈ کروزر لے کر آ گئے۔ جوان کی حالت بری ہوئی، دوسرا نعرہ 'غریبی ہٹاؤ' آیا۔ غریب دوگنے ہو گئے، غریبی نہیں ہٹی۔ تیسرا نعرہ 'اچھے دن لاؤ' آیا۔

---

†Transliteration in Urdu Script.

مانّنے اپ سبھا پتی مہودے، یہ کسانوں کا دیش ہے۔ اس دیش کی دھرتی ماں کا سینہ پیاس سے پھٹ رہا ہے۔ سوکھے کے دن ہیں۔ کھیتوں کی سنچائی کے لئے ایک ہزار کروڑ روپے دنے گنے ہیں اور 60 ہزار کروڑ روپے اسمارٹ شہروں کے لئے دنے گنے ہیں۔ میں اس سے ایک مثال ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ مٹھی بھر لوگوں کے لئے بنا ہے۔ بجٹ سے نوجوان مایوس ہوا ہے، جو 43کروڑ ہے۔ میرے ہی ایک سوال کے جواب میں کہا گیا تھا کہ جس کی روز کی آمدنیی 32 روپے آنکی جاتی ہے، پہلے یہ 28 روپے آنکی جاتی تھی۔ مہودے، میں ان پریواروں کو جانتا ہوں۔ جن میں میم صاحب کا کتّا 28 روپے سے زیادہ کا کھانا کھاتاہے۔ اگر ان 43 کروڑ لوگوں کو بجٹ نے مایوس کیا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ودوان بھائی اور مانّنے جیٹلی جی، جن کی بدھمتا کو دیش سلام کرتا ہے، شاید ان کا بجٹ کسی کے دباؤ میں بنا ہوا بجٹ ہے۔ اس لئے ہندوستان کا غریب نوجوان، مسلمان اس سے مایوس ہوا ہے۔ کسان مایوس ہوا ہے۔

مانّنے اپ سبھا پتی مہودے، میں مانّنے وتّ منتری جی سے انورودھ کرتا ہوں کہ دیش کے بہوسنکھیک کے سامنے رکھہ کر، نعروں کے بجائے دیش کے بہوسنکھیک سموداے کو سامنے رکھہ کر، ان کی غریبی اور ان کی تکلیف کو دیکھہ کر، اپنے بجٹ پر ایک بار نظر ثانی کریں۔ میں بجٹ کی آلوچنا سے زیادہ انہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ مٹھی بھر لوگوں کے لئے بنایا گیا بجٹ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ نے مجھے اگر ایک منٹ بھی دیا تو میں کہتا ہوں کہ انقلاب برپا کرنے کے لئے بہت ہوتا ہے ...(مداخلت)... میں دیش کو بتانا چاہتا ہوں کہ ...(وقت کی گھنٹی)... (مداخلت)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yout time is over. Please sit down, since the mike is off, it is not going on record. ...*(Interruptions)*... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... it is not going on record. ...(**व्यवधान**)... बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)... श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद। ...(**व्यवधान**)... मुनव्वर सलीम जी, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, आपने माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

MR. MEPUTY CHAIMAN : Don't waste your time on 'dhanyavaad.'

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, पक्ष-विपक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं। आज आजादी के 67 साल होने जा रहे हैं। हमारा देश किसानों का देश है। 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। जब तक गांवों की तरक्की नहीं होगी, खेती-किसानी की तरक्की नहीं होगी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। आज गांवों में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। किसानों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। किसानों के लिए बिजली का इंतजाम होना चाहिए, खाद का इंतजाम होना चाहिए और सिंचाई का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन यह सब नहीं हो पा रहा है। आज गांवों में रहने वालों के लिए रहने को मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है।

सर, मैं बुंदेलखंड के बारे में बताना चाहता हूं। बुंदेलखंड में आज भी लोग नदी का पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। आज सूखे के कारण वहां जमीन में दरारें फट रही हैं। लोग पांच-पांच किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। वहां के बारे में पाठा क्षेत्र के बारे में कहावत है कि 'हमारी गगरिया न फूटे, खसम चाहे मर जाए'। मतलब वहां पानी इतना कीमती है कि पति चाहे खत्म हो जाए, लेकिन हमारी गगरिया न फूटे, हमारा पानी न बरबाद हो। पानी के लिए युद्ध हो रहा है। मान्यवर, वहां जंगली जानवर इतने ज्यादा हैं कि जो किसान थोड़ी बहुत फसल उगाता है, उसे नीलगाय खा जाती है और किसान पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बुदंलखंड के लिए पिछली गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज दिया था, लेकिन उससे काम पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज देकर वहां के लिए पानी के बारे में सोचा जाए। वहां पर कृषि बरसात पर आधारित है। इस साल पानी नहीं हुआ, जिसके कारण खरीफ की फसल नहीं हुई। बुन्देलखंड तिलहन और दलहन के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर बिना पानी के गेहूं पैदा होता है, कठिया गेहूं पैदा होता है, जिसको पूरे देश के लोग मंगाते हैं, क्योंकि यह पौष्टिक होता है और डायबिटीज के लिए फायदेमंद है। इसी तरह की शोध करके बुन्देलखंड में कृषि को बढ़ावा दिया जाए।

मान्यवर, सरकार पी.पी.पी. और एफ.डी.आई. पर ज्यादा ध्यान दे रही है। हम कहना चाहते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश में व्यापार करने के लिए आई थी, वैसे ही ये विदेशी पूंजी को यहां पर लगवाने का काम करेंगे, विदेशी कंपनियों को यहां लाएंगे। जो विदेशी कंपनियां अपने देश में डिफॉल्टर हो चुकी हैं, वे कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए आ रही हैं। भारतीय बाजार में चाइना बाजार छा गया है। इससे हमारे जितने भी उद्योग-धंधे हैं, वे सारे बंद हो जाएंगे। जब कभी ऐसी स्थिति आएगी, जैसे सीज़फायर हो रहे हैं, सीमा का उल्लंघन हो रहा है, जब पूरा व्यापार बंद हो जाएगा, हमारी सारी कपड़ा और पेपर मिलें बंद हो जाएंगी, तो हमारा देश तबाही के कगार पर आ जाएगा। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay, please sit down, the mike is off. Shri Husain Dalwai.

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra) : Sir, thank you very much. सर, मैं सिर्फ प्वइंट्स रखूंगा। इस गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात यह की है कि उन्होंने Ministry of Minority Affairs का एलॉटमेंट 600 करोड़ से बढ़ाया है। इसके लिए मैं जेटली जी का आभारी हूं। उन्होंने मदरसा के लिए सौ करोड़ दिया है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मदरसा चलाने वाले चलाते हैं, उनको चलाने दीजिए, लेकिन आज मुस्लिम समाज मॉडर्न स्कूल में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है और बीते दस साल से हमारी यह मांग है। पूर्व गवर्नमेंट यानी हमारी गवर्नमेंट से भी हमारी यह मांग थी, हमने महाराष्ट्र सरकार से भी मांग की थी कि उनको स्कूल दीजिए। आज जो चाइल्ड लेबर फोर्स है, उनमें 78 परसेंट मुस्लिम समाज के हैं, क्योंकि इस समाज में इतनी गुरबत है, इतनी गरीबी है। आज वह पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है। आप ऐसा कीजिए कि हर जिले में कम से कम एक residential school ऐसा बनाइए, जिसमें सारी बातें हों। वहां उनको खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, खेलने की सुविधा मिलेगी।

सर, दलित और आदिवासियों को जो सुविधा शिक्षा में मिलती है, वही उनको दीजिए। वे गरीब मुसलमान हैं। मैं जब मुसलमान बोलता हूं, तो मेरे दिमाग में अमीर मुसलमान बिल्कुल नहीं रहता है, गरीब मुसलमानों के लिए मैं यह बात कर रहा हूं, इसलिए आप इसको दीजिए। टीचर्स को दो-तीन साल से honorarium नहीं मिला है, उनको पेमेन्ट मिले, इसको आप देखिए।

सर, Grants-in-Aid to Maulana Azad Educational Foundation के जरिए गरीब मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, उस मद में आपने उसको 47 करोड़ से कम कर दिया, है, उसको कम करने के बजाए उसको बढ़ाइए। आपने नॉर्थ रीजन की बात की, नॉर्थ रीजन में भी आपने 72 करोड़ रुपए कम किए हैं। Maulana Azad National Fellowship for Minority Students, जिसके अंतर्गत Post-Graduation, Ph.D. के लिए मदद की जाती है, उसमें भी आपने पांच करोड़ कम किया है। Scheme for Leadership Development of Minority Woman के जरिए औरतों के लिए क्या-क्या स्कीम है, वह बताने के लिए लीडरशिप तैयार करने का काम होता है, उसमें भी आपने कटौती की है। इसमें कटौती मत कीजिए। Maulana Azad Medical Aid Scheme, आप यह एक नई स्कीम लाए हैं, यह बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। Pre-Metric Scholarship for Minorities में भी अपने बढ़ोतरी की है, Post-Matric Scholarship for Minorities में आपने बढ़ोतरी की है, इन सबके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन जहां कटौती की गई है, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the mike is off. Please sit down, since the mike is off, it is not going on record. Shri Jesudasu Seelam.

9.00 P.M.

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, I just want to make three quick points. One is regarding allotment to Andhra Pradesh. Second is on the Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan, and the third is on the Vision Document that is proposed by the former Finance Minister.

Sir, on the Andhra Pradesh side, as you are aware, the Bharatiya Janata Party, especially Shri Arun Jaitley also was very categorical that they would provide necessary assistance when the opportunity comes. Among other things, the Prime Minister spoke in this House to give compensation for loss of Hyderabad revenues. Unfortunately, we will be losing ₹ 17,000 crores. So, it was assured that something not less than ₹ 10,000 crores would be provided in this Budget. Unfortunately, that is not forthcoming.

Secondly, Sir, the UPA Government, while agreeing to the request of our friends from Telangana, ensured that the residuary State of Andhra Pradesh would not suffer from the infrastructural facilities, like NIIT, IIM, IIT, NIT, IISER, agricultural university, tribal university, a port and other institutional facilities. But, what is the allocation made for this purpose? I am very sorry to say that a token allocation of Rs. 1 crore each is made. That is not at all sufficient, Sir. Unfortunately, the Bill provides for substantial amount to be allocated for establishing the Capital. Sir, nowhere in the Budget is the amount indicated. Sir, it is high time that the hon. Finance Minister in his speech may come out as to how much is going to be allotted for building of the Capital and also for various educational institutions.

Sir, as far as AIIMS like institute is concerned, he has clubbed Andhra Pradesh with West Bengal, Uttar Pradesh and Maharashtra, and all the four States together have been given Rs.500 crores. Sir, this is very, very meagre. Sir, we will not be able to present our Budget this year. So, for meeting the deficiency, he has to announce that, Sir.

Secondly, for the SCSP & TSP, I am happy that Arunji has given boost as it is. He has continued the UPA's process of the Sub-Plan. But, ensure that the amount is spent. That is the problem. Money is allocated, but not spent. Even if it is spent, it is not spent for the right purpose. Even if it is spent for the right purpose, there is a lot of cutting at various stages.

Sir, my last point is the 10-Point Agenda which the former Finance Minister, Shri P. Chidambaram gave on fiscal deficit, current account deficit, price stability and growth, financial sector reforms, infrastructure, manufacturing, subsidy issues, urbanization, skill development and cooperation with the States. Sir, GST has to be brought.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, sit down. Now, Shri Bhupinder Singh.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Three minutes are over. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. Mr. Bhupinder Singh, you start speaking. ...*(Interruptions)*... That is not going on record. ...*(Interruptions)*... Sit down. Mr. Bhupinder Singh, you start. ...*(Interruptions)*... Three minutes means three minutes.

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha) : Mr. Deputy chairman, Sir, the General Budget for 2014-15 has three aspects.

इसमें तीन चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर एंड इरिगेशन। हमें इन तीनों सेक्टर्स को जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी उतनी हमने नहीं दी। अर्थ मंत्री जी, हमारे पास जो साधन हैं, उन साधनों के बीच आपने कोशिश की है, लेकिन इन तीनों के ऊपर ज्यादा जोर देने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। सर, अगर इस देश के किसान के चेहरे पर मुस्कान है तो सरकार के चेहरे पर मुस्कान है, अगर उसके चेहरे पर मुस्कान है तो देश के चेहरे पर मुस्कान है और अगर वह रोता है तो देश रोएगा, आगर वह रोता है तो सरकार को भी रोना पड़ता है। हमारी जो अर्थ नीति है वह फार्मर्स और टूरिज्म बेस्ड है, यह बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए।

अर्थ मंत्री जी, मैंने कल स्पेशल मेंशन में यह बात कही थी कि हमें इस बात पर सीरियसली सोचना चाहिए कि हर सेकंड में हमारी जमीन जिस तेजी के साथ कम होती जा रही है, land is reducing, उतनी ही ज्यादा जनसंख्या-वृद्धि हो रही है। 2.3% of total land available in the world is available in India. Seventeen per cent of thr total population of the world is in India. इसलिए आज इंडिया का साइज ऐसा होना चाहिए, जिसमें 22 करोड़ जनता रह सके। हम मार्स, मून, जुपिटर, जहां भी जाएंगे वहां इंसान नहीं रह सकेगा, यह साइंटिस्ट्स भी कह चुके हैं। इसलिए मैं आपसे और इस सदन के सारे सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमने जमीन के लिए नहीं सोचा तो देर हो जाएगी। आज किसान की जमीन कम होती जा रही है। और उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइम है वह क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? उसके ऊपर जोर दीजिए। समालोचना करने की यह सभा नहीं है। आज बजट में जितना अधिक ला सकेंगे यह सब के भले के लिए होगा, देश के भले के लिए होगा। हम यहां पर के.बी.के. के लिए बोले हैं और हमारे मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने और हमारी सरकार ने करोड़ों लोगों को लाकर यहां दिल्ली के दरबार में इकट्ठा किया कि हमें स्पेशल केटेगरी स्टेटस चाहिए। के.बी.के. का जो जोन है उसके लिए आप ज्यादा पैसा हमको दीजिए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना 2010 में खत्म होनी थी, टेंथ प्लान, इलेविंथ प्लान और ट्वेल्थ प्लान में आकर उसको कब तक खत्म करेंगे? उसके लिए मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आप उसकी तरफ ध्यान दें। फूड सिक्योरिटी की जो बात है, उसके ऊपर आप चुप रहे। मनरेगा के लिए आप क्या करना चाहते हैं, यह आप अपने जवाब में स्पष्ट करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बजट का जो मेनेजमेंट है, जब तक हमारा केपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है, तब तक कोई एसेट्स नहीं बन सकती हैं। मनरेगा में हमारी एसेट्स नहीं बन रही है, मनरेगा में हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे ही जा रहा है। ...(**समय की घंटी**)... ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हो गया, हो गया। ...(**व्यवधान**)... बस, श्री मिनट्स हो गए। ...(**व्यवधान**)...

DR. PRABHAKAR KORE (Karnataka): Sir, I welcome the Budget which is the 21st century Budget. I would like to tell the hon. Finance Minister that cooperative sector is totally forgotten in this Budget. About 110 ten years ago the first cooperative sector was started in Karnataka contributing finance to the cooperative sector including banks, sugar factories, urban banks, rural banks, etc. These are all in the cooperative sector. When the UPA Government was there, they imposed Income-tax on the cooperative sector. It is for the last six years that the cooperative sector is fighting for exemption in this regard. I request the hon. Finance Minister just to look at it so that cooperative sector can survive in this country, which is very important.

Secondly, Karnataka has been a pioneer in producing engineers starting from Vishveshwarya. We have given very good technologists throughout the world and because of that the IT sector has come up in Bangalore. I only request that for a very long time we have been waiting for an IIT which is very, very essential for Karnataka particularly in Belgaum because Belgaum has started an SEZ manufacturing aircraft spare parts including hydraulic system of Boeing Airbus and many other companies. It is a very big industry in Belgaum. Belgaum is the second largest foreign exchange earning district in Karnataka. So, I request for this IIT. If it comes up in Belgaum, it will be very good. Sir, Karnataka is waiting for a very, very long time for this.

Thirdly, another much more important thing is about the sugar industry. Sir, farming is totally based on sugar industry. Nothing has been mentioned about sugar industry. Sugar industry is in a very, very bad shape in Karnataka, U.P. and other places. So, something must be done by the Government in the form of subsidy or something like that. Whatever interest exemption has been given it is not enough. I request the Finance Minister to look after it. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I request the hon. Members not to quote it as a precedent because there is a direction from the Chairman that names received after half-an-hour from the commencement of the discussion should not be taken. This is only an exception because it is Budget. Please don't quote it as a precedent. Now, hon. Finance Minister.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, the Finance Minister presented a Budget within 45 days of his taking over charge; a Budget which, very clearly, sets the direction for what is to come in the next five years; a Budget -- however much the hon. friends from the other side would want to believe -- which was prepared in spite of a situation which was not very favourable for any Finance Minister

to present his first Budget; a Budget which was to be presented, especially when the expectations were very high, hoping that the direction of the economy or the direction in which the economy should move towards fulfilling the aspirations of the young voters, general citizens who have been let down in the last ten years, wondering what was going to happen, not purely due to domestic compulsions, but also because of international financial situations. In such a situation, in which expectations were rising and were very high, a change of Government happens; and, a change of Government happens, especially under the leadership of a person who had headed a dynamic States, winning popular mandate three times over, and each time fulfilling everything that was promised in the manifestoes. So, naturally the expectations -- to present a Budget within 45 days in a situation where the economy was at its sluggish worst, and to also build up hopes, saying that this economy could be steered and steered in such a way that hopes of people can be met, but not just by saying in words, but putting money, very little of which was available, in such sectors that could give a direction to the economy -- were very high. Therefore, I stand here with a sense of pride for having worked with a person who has slugged it out to see how best the Budget could be brought in as a 'document of hope' and making sure that the message reaches everybody. I have had the fortune to listen to each one of the speakers with great sense of attention, a lots of inputs have come, ranging from this Budget could have been a lot more creative, at the same time, to conceding in talking about taxation, in talking about opening of newer opportunities. There have been a lot of concessions and a lot of complementary words for which I am very, very grateful. At the same time, I have also heard criticism, which I would take in my stride; and, I am sure, the hon. Finance Minister also would be able to, when he speaks, express his views on it. But I thought if I can be allowed that margin, which were largely emerging out of uncertainty in mind, people were not sure whether they wanted to compliment for the Budget and the limitations in which it was presented. They were not sure whether they wanted to appreciate it. At the same time, they were also confused and saying that we were only continuing their job. To me, it was a bit difficult to accept, knowing the conditions in which the Finance Minister has Come out with a Budget of this nature and showing very clearly a simple and a low tax regime. Comments have been made that we were trying to please the middle class, neo-middle class and so on. Be that, as it may, it is a Budget which has been prepared with severe constraints, which is apparent to all of us. It is not a secret. Comments have been made that the economy is at its sluggish worst. But, at the same time, with resource constraints to different sectors, be it Rs. 50 crores or Rs. 100 crores, Rs. 100 crore allocation to ten different sectors need not be looked at with a sense of dismay or dismissive of such an allocation because this is not an unusual practice. The Budgets of 2011-12 and 2012-13, I am sure, the Members of other side would know, have

[Shrimati Nirmala Sitharaman]

had several hundred crore allocations. Did we think that they were just token gestures? No. Did we think that they were just symbolic? No. No. We thought that they were important allocations made to start up with something, or, to invest in something which could grow eventually. So, I think the same generosity and the same magnanimity with which those kinds of allocations were made with Rs.100 crores or Rs.50 crores should be extended to the hon. Finance Minister too, because this is an allocation made when the resource constraints are very clear. At the same time, allocations made at a time when you are germinating with an idea which could in the long run absorb it. But to say that these are petty allocations, small allocations, or insufficient allocations, I would think they have come out of a haste in criticizing it, but the situation demands that we look at it both, from the point of view of allocations made to start off with something and allocations made, yes, symbolically, but to germinate an idea and above all, allocations made in difficult economic circumstances. So, I don't think they are new and I don't think they are first time. Since this has happened even earlier, I think that allowance must be given to the Finance Minister. Above all, I think there are many such allocations made on which I think we need to understand why in this kind of a situation, we are placing emphasis on job creation. Continuously, we have heard of growth, growth happening over the last five to ten years, a growth, which according to the Government data has been jobless. I can see hon. Member, Shri Anand Sharma, shaking his head trying to negate my point, but it is a fact which has come out of an NSSO zone data, therefore, I rely on the Government's data to say that it didn't produce as many jobs as it should have. The emphasis given in this Budget, therefore, is on creating incentives for providing Rs.10,000/- crores for start ups, that is a major step and I would credit the Finance Minister for having taken the step towards it.

The other most important point which I think one of the Members from JMM had mentioned is about the funds under Compensatory Afforestation Fund (CAMPA) lying outside the purview of the Parliament. The Government is aware of the huge amount of resources locked up outside the Consolidated Fund and is contemplating bringing in a suitable law to bring this amount within the legislative purview. I need to underline that because it is a very, very important point. I also with due modesty raise the point which the hon. Member, Shri Naresh Agrawal, had mentioned that in the preparation of this Budget, he wished the Chief Ministers were consulted, he wished that States were taken on board in consultation. I take this opportunity to bring to the notice of the hon. Member that not just once, twice the Finance Minister sat with the representatives, Finance Ministers from all the States and discussed with them before the Budget document was prepared. Consultation was also held on the GST. So, let me assure the hon. Member

that it was not devoid of States' inputs and it was not without the consultation with the States. So, that is the point which I would like to draw your attention to. One of the things which I would, certainly, like to underline is several hon. Members have raised the issue of action taken by the Government on black money. I am sure by now, all of you would remember that the first subject matter of this first Cabinet was to create an SIT. .That was the first major decision taken by this new Government. I would like to put that on record. Members have also raised issues regarding FDI in defence. I would like to mention that defence production with 51 per cent Indian ownership is much better than having 100 per cent foreign ownership, but buying it from abroad, paying through our nose literally, with foreign exchange going away. So, I think that is a major step which this Finance Minister has taken for which I would, definitely, commend him. There are one or two other small additions which I would like to say in terms of assurances, in the sense not really assurance but it has been mentioned in the Budget so. Several Members have raised questions about allocations for newly created States such as Andhra Pradesh and Telangana. In the Budget, we have tried to address the concerns of both the newly created States and needless to state here that the Union Government is committed to providing full support to both the States.

Lastly, without taking much of the Finance Minister's time, I would like to say in the current fiscal year, we plan to extend agricultural credit because a lot of hon. Members have raised issues on agriculture. I would like to say that we plan to extend agricultural credit to the extent of ₹ 8,00,000/- crores. This is nearly ₹ 1 lakh crore more than planned for the financial year of 2013-14 in the Budget. We hope to surpass, the target set for this current financial year. Lastly, the Finance Minister has announced to support drug de-addiction centres in Punjab and an initial amount of ₹ 50 crore was proposed in the Lok Sabha. The same shall be provided to the State of Punjab which is fighting the menace of drugs, in due course. So, with these few words, I would plead with the House to support this Budget. I think it is a good work in difficult circumstances and within 45 days of taking over. So, I would beseech all of you to full-heartedly support this Budget. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Finance Minister to reply. *...(Interruptions)...*

SHRI ARUN JAITLEY: Mr. Deputy Chairman, Sir, just a few words to what my colleague has said. Sir, 56 speakers have spoken in the last two days on this Budget. The discussion was very ably initiated by Shri Anand Sharma who has an experience of having served as a senior Minister in the UPA Government and, therefore, he knows the difficult challenges which confront the Indian economy. I would most earnestly urge

[Shri Arun Jaitley]

the House that there are issues of national security, there are issues of foreign policy so also there are issues of management of the economy, a large part of which can be kept outside the partisan discourse. It was mentioned repeatedly, well, this Budget has several ideas which belong to the earlier Government. In fact, some of my Members sitting in the middle commented that some ideas are common. When my friends of the Congress Party suggested it, I was very happy because I thought they are going to support the Budget because these were their own ideas. But their having claimed these to be their own ideas or having claimed the copyright over these ideas, I think, they were grudging something, and the grudging fact is not that somebody from here has said that nothing has been done in the last ten years. There were difficulties in the last ten years. The earlier Government could have been more decisive. It could have avoided a drift in the policy; it could have taken steps when the. environment of the economy got hijacked by certain kinds of scandals. Retrospective tax virtually became a defining moment when the investors decided to desert us. The credibility of the Indian economy came into question and, therefore, when a change of Government took place, there are several challenges. We cannot go back only to the glory of the past and say this is not a challenging situation. The last two financial years have seen a sub-5 per cent growth. Now, it is true; this was the lowest in the ten years of the UPA. The earlier eight years had a much better growth rate. But this is the growth rate which was left behind and, therefore, when you have a sub-5 per cent growth in an Indian economy, the spiral consequences of this are serious. Economic activity contracts; it doesn't expand; job creation doesn't expand; the manufacturing sector was flat in one year and negative in the other year. And, when the manufacturing sector goes down, new jobs are not being created, Custom Duty collections will go down, Excise Duty collections will go down, and the tax buoyancy itself goes down. Therefore, if the tax buoyancy itself goes down, the entire expenditure of the Government on servicing itself, on servicing the social sector schemes, goes down. There is not enough money in the pocket of the Government as the savings rate goes down. Our savings rate has come down to almost 29-30 per cent, which is low by Indian standards. Our subsidy burden is reasonably high. That is the situation which we are confronted with and, I think, what was most challenging was that the mood in which the economy was being administered, that mood itself had declined. So, how does India bounce back to those days of 8 per cent and 9 per cent growth rates? That is the real challenge. In this challenge, Sir, what is broadly the course that India follows? To a highly-regulated economy, we said good-bye in 1991. I am happy we did that. I would have been happier if we had done that a decade or so earlier. Since then, broadly, we have

Governments of different political colours. They have had different policies. There are a few issues on which we may manufacture differences, but the differences don't exist. Does anybody in this House say that India must not have a high growth rate? We are all *ad idem*. We are of the same opinion that we must have a high growth rate. We must allow the State's role in administration of the economy. We must also allow our private sector to grow. We need investment. We need investment from within the country and we need investment from outside also. Now, we can have genuine differences and we do have those differences as to which sector should be opened, which sector should not be opened for foreign investment. But then, we have to accept the principle that when investment from within is inadequate, FDI is an additionality of resource. If you have no investment, you won't start economic activity. So, it is essential that we have an adequate amount of investment in the country. Investment itself will lead to economic activity. It will lead to job creation. We must have investment resulting in profitable economic activity. We have now reached a stage where 'profit' is not a bad word. Unless there is profit, there won't be taxes. So, the Governments need to have enough revenue in their pockets. This revenue is used then for creating infrastructure and for strengthening social infrastructure. Our poverty eradication won't take place merely because the growth rates are high. There will be some pull-up effect. People will get pulled out of poverty, but that won't be sufficient, and, therefore, we all try and use this additional resource in the pocket of the Government for poverty alleviation schemes. And, if we are able to create a good environment, which Members have referred to, there will be ease of doing business in India. India, being an investment destination, if we can attract both, investments from within and outside, we will need a good infrastructure that leads to a larger economic activity. This is how the Indian model has functioned. Now, when this Indian model functions, if investment dries up, if our economy fails to inspire the world, and forget the world outside, if it fails to inspire the entrepreneurs within the country, and we have seen in the last few years a reverse flow of investment taking place, we know the investor is also the chooser. If we don't create an environment to attract him, then he will look at other sources, whether it is China, or, it is Indonesia, or, it is Thailand. He also has a choice, and, that's not only the international investors; that's also our Indian investors. We cannot afford to let them go. So, I think, there has to be a concentrated national effort to make sure that this investment gets concentrated within. It is too early to say that the situation which was challenging, we are able to get out of. I think, it is too early to say that. There are some indications and these indications are very preliminary. From a negative growth rate in manufacturing, the index of industrial production was up 4 per cent in April-May, and, up 4.7 per cent in June. It is only a small initial indication. In February, for a period of three months, my predecessor gave some excise duty concessions to the auto sector, to capital goods,

[Shri Arun Jaitley]

to consumable durables, in the hope that the manufacturing sector, which was negative, will pick up. Those were to expire on the 30th of June. I have extended them now till the end of the year. Some result is visible. The June figures of auto sales, etc., have all moved up, and, if they move up, that means, the manufacturing sector is getting back into action. Some improvement in the import of capital goods and raw material is there. Now, gone is the conventional thinking when people thought that imports are generally bad for the economy. If raw material and capital goods are coming into the economy, it is a good sign because that means in the months to come, manufacturing will pick up. Our manufacturing sector is now importing raw material. There are capital flows, exports. Some moderation, I won't say very large but some moderation is seen. The June figure of the Wholesale Price Index is 5.43 per cent; the Consumer Price Index is 7.31 per cent, the lowest in the last 30 months. These are only initial indications.

It is from this that we really have to pick up. Why is the Budget proposal a little different? Sir, I have moved on the assumption and on a premise that low taxation is good for the economy, and, therefore, in this Budget, as a rule, whether it was customs duty or it was excise duty, in order to give a fillip to the manufacturing sector, some duties have been brought down. People want to buy goods, they don't want to buy taxes. Taxes increase the cost, and, therefore, if the cost goes up because'of additional-taxes, our products will become non-competitive in the domestic market, they will become non-competitive in the international market. Therefore, as a rule, I do believe that unless there are some special circumstances to make the economy more viable, and, it is very easy to go into slogans as some of our friends said that you favoured the business. Let me make a candid confession. If you say that I have helped the businesses, and, this Budget is pro-business, yes, it is. I have no hesitation in saying that it is pro-business. Does it help the middle-class, does it help the neo-middle class? It does. Does it help the poor? It does. There is no contradiction in an economy that if something encourages industrial activity in the country, it is bound to be anti-poor. You need to be pro-industry. It is only then that you will gather sufficient revenue so that you are able to service the poor in the country. There is no contradiction and we have moved on this erroneous presumption, at least, some of us, I can say. Now, I have been hearing an argument -- a few days ago, earlier also, I addressed it -- and, particularly, my friends from the Left do it. Taxes are being forgone. Now, a practice started several years ago, and it picked up when UPA was in power, that a booklet comes with the Budget which says 'list of taxes forgone', and some five lakh crore rupees are mentioned. Now, these are not taxes which were due, these are not taxes which are to be collected and we are being in collusion with the person not collecting it. These are taxes, for instance, if the bound rate of a product is 70 per cent but an applied rate is

40 per cent, then 30 per cent is notionally taken as tax forgone because if your rate was 70 per cent, then probably the product would not be going to be manufactured at all. Now, under section 80 (C), one lakh was the rebate given. I have increased it to one-and-a-half lakhs. That is tax forgone. So, in giving rebates to the middle class, I have forgone taxes. So, tax forgone actually means in the larger interest of the economy, you are making it more competitive. These are not taxes which are due from people and which we are deliberately not collecting. This was the practice when UPA was in power; this is the practice when the present Government is in power. Therefore, I was mentioning that as a rule we had a moderation in the taxes itself. I have consciously taken a large number of steps both in terms of the fiscal policy as otherwise to give encouragement to the manufacturing sector. The sunset clause is for investment in power. If there is no power in this country, if power production does not pick up, our industrialization won't take place. So, I have extended the sunset clause when power sector rebates in taxation are given. Investment allowance used to be given to whoever invested rupees hundred crores. I said, 'no, it should be given to whoever invests twenty-five crores'. So, even the MSME sector, the middle-level industries, when they invest rupees twenty-five crores, they will be entitled to incentives. This is all intended to encourage the manufacturing sector. When you set up textile clusters -- and a large number of Members have said, please do that in our State. I am going to consider each of those States, depending on the availability of resources -- in a small way, they create jobs. When you say Bareilley, it is the zari industry; Lucknow, it is the chicken cotton; the weavers, the bunkars, of Varanasi, the *pashmina* manufacturers of Sri Nagar, whether it is Surat or it is Odisha or it is Tamil Nadu or Kerala, these are all areas where .people at the grassroots have got talent. If we are able to provide some sum of money by which these products can be advertised and marketed in a larger market, that is the whole idea of a cluster that people have developed talent in those areas, the manufacturing itself picks up. The investment allowance encourages manufacture. The start-up fund for the MSMEs, Rs. 10,000 crores, is intended to encourage manufacture. 'Industrial corridors' was an initiative that the UPA Government started. I have adopted that initiative and I intend to continue it. Electronic goods, we have given a relief to. So, unless you are able to expand our manufacturing, those are serious problems, and I am not saying it in an adversarial manner, with regard to the taxation policy, which was followed by the UPA Government. And I will tell you what the problems were. I have already mentioned that the retrospective tax was a retrograde idea. It was retrograde because it sent a very negative signal to the world of investors. Investors started drying up after the retrospective tax. In fact, when the UPA Government was in its last days, I was hoping against hope that they find a solution to solve this problem and then go away. But you left the knot tied up and left it to us to untie the knot, and it is a very difficult knot to untie.

[Shri Arun Jaitley]

So, we announced in the Budget that we recognize that Indian Parliament has the sovereign right to legislate retrospectively. As a policy, our Government won't use that power. If on account of your 2012 Bills, new notices are to be issued, the assessing officers will not issue them. We have created a mechanism under the CBDT. It will be referred to that mechanism. The idea is not to create fresh controversies on retrospective tax. And the big challenge was: What do we do with regard to the litigations which are already pending as a result of 2012 retrospective law? There were two possible views. Either by legislation I decide those litigations against the Government or I allow the litigations to be contested on the forums on which they are being contested. We consulted various people and finally found that the second course was more prudent. Legislation is a methodology of following disputes and so is the legal methodology is a course of following disputes. We have left it to that.

On FDI, my friend Anand Sharmaji was right when he said that we were reluctant when they brought the proposal of 49 per cent in insurance. But that is only half the truth. I think I must place the full truth before you. The idea of 49 per cent was first conceived by the NDA Government. When we consulted the then Congress Party, we were told that the Congress Party was only prepared for 26 per cent. So, we stepped back on our 49 per cent proposal because we needed your support and you were only agreeable to 26 per cent. Wisdom dawned on you when you came to power and said that you were agreeable to 49 per cent. By December last year, we made considerable headway. Mr. Chidambaram was discussing the issue with my colleague Sushmaji and I. But then the elections came and the Government changed. We had therefore gone back to our original proposal which you had also accepted which is 49 per cent subject to Indian majority and Indian control in the management.

The insurance sector is investment starved. Our health sector is not picking up because it is not backed by insurance. You know what happens when somebody gets admitted to a private nursing home for surgery for a few days or in the ICU. How much of the back up insurance do we have in this country? Do we need to expand that insurance or not? That is a decision we have to take. And it is not a question of their proposal which we are now accepting it. That is a hard reality. We need to expand insurance in several areas.

In Defence, the current position is that we are today importing directly or indirectly 70 per cent of defence requirement from international suppliers. We buy it from companies outside India. The suppliers are either hundred per cent foreign government-owned companies or foreign private companies. Our defence requirement of seventy per cent

comes from-foreigners today. When the NDA was in power, we said that 26 per cent was the defence limit. The UPA amended that policy and said that 26 per cent but on a case to case basis it could be higher. It could be even higher than 49 per cent subject to FIPB approval and Indian control and subject to CCS approval in certain cases. We have examined this policy. A lot of investors, who have technology and investment outside, are willing to come. Indian capacities have also slightly built up. There are some of our major corporates, and I can name some of them because they are at my fingertips, and large reputed groups in India which have now built up defence capacities for manufacturing in India. We have further evolved the policy to say that it would be 51 per cent Indian and the foreign investment can go up to 49 per cent and this will be subject to usual terms and conditions which will be finalised by the Government when the issue comes up before the Cabinet. Now, we have to consciously decide which one is a better situation. We buy everything from foreigners outside. Is that a better bet for our national security or we set up companies controlled by Indians in India in addition to the public sector and the defence PSUs that we have and start manufacturing in India? Ultimately, India has to have a defence production capacity inside the country itself and that is extremely important as to why we need that capacity in India. We will save foreign exchange; we will build up our domestic capacity. I can tell you that one of the first decisions that we have taken in the Defence Ministry when the Air Force wanted to buy 58 transport aircraft is that we opened the market to Indian private sector so that large companies in the Indian private sector find their partners from abroad. Indian company will be the larger partner and for the first time, those 58 transport aircraft will be manufactured on Indian soil by companies with an Indian majority. It is much better than buying them from outside and bringing them to India. That is how the Indian capacities will be built up in defence.

Sir, then, I come to bank capitalisation decision. Today, in terms of financial inclusion, the banks reach only 58 per cent of our population. Forty-two per cent people have no access to banks. Banks have to expand their branches into many, many more areas. So, we have decided that we will maintain the public sector character of our banks. Some of the surplus holding, while maintaining the public sector character, which is 51-52 per cent, can be offloaded by the banks into the market so that small investors pick them up. To beat Basel-Ill norms by 2018, we intend to raise ₹ 2,80,000 crore by which financial inclusion, the reach of banks, from 58 per cent at present, goes up to 60, 70, 80 and 90 per cent and as much as it can. That is the capacity. Ultimately, farmers, tribals and people who need micro finance will have access to those banking facilities. That is one of the ways of addressing poverty. People will get their source of funding to do some economic activity as far as they are concerned.

[Shri Arun Jaitley]

Now, in respect of visas, we have taken a small decision, but it is a far-reaching one. Barring certain countries, because of security considerations, we have expanded the concept of visa-on-arrival and electronic visas. The tourism sector feels that this decision itself has the capacity to substantially increase the number of tourist inflows into the country.

My friend, Mr. Sharma, took note of the Real Estate Investment Trust. He made a comment quoting Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister, who was sitting next to him that in real estate, we have to be a little cautious. Now, a Real Estate Investment Trust is an experiment which has been tried in various countries. In India, it had not succeeded because when it was considered earlier, pass-through tax rebate was not granted. We have granted that now and I hope it takes up. To encourage real estate, we have got several other suggestions in the Budget itself. Now, you are right that in Japan and Dubai, during the sub prime crisis, it did become a bubble which burst. But, it became a bubble to burst in those economies which were saturated with real estate and were moving from saturation to super-saturation. In a country where 60 per cent people still have to have access to housing, who are either living in slums or in village huts, in a country where, if not hundreds, dozens of townships have to come up in the next few years, is there any option that we have other than saying that we need to encourage real estate, we need to encourage sub-urbanisation and we need to encourage urbanisation? Millions of people still have to come out of village houses and come into suburban towns, start living in apartments and buildings and in regular houses. Therefore, in foreseeable future that burst is hardly likely, because we are saturated with real estate. In fact, at the moment we are far behind what our targets are. I take notice of the fact that we have to be very careful in the matters of real estate. But the bubbles are burst in economies which have been super-saturated with real estate itself.

Sir, I am not counting all the areas, but in agriculture, in the social sector, in the infrastructure, there is not a single area where we have reduced the allocations itself. In each of these areas we will come out with some innovative ideas; and continue some schemes. I have no special affinity to 100 that people say, "why did you allocate ₹ 100 crores." I could have even allocated Rs.1 crore. I thought that, at least, my friends in the Congress Party would be able to appreciate this. They have been in power for a long time. When a Government launches a scheme, you have to make a token grant against it. The allocation is the start of a scheme. I have seen many Budget speeches where schemes have been started with one crore rupees, nominal allocation. But once the proposal is made, and the scheme will be implemented, and whatever money is required for the scheme, comes out of the budgetary funds.

I will give you an illustration. We said that West Bengal will have an All India Institute of Medical Sciences. This year we have decided to give them ₹ 100 crores. I know that ₹ 100 crores is not enough for an AIIMS. But this year one-third of the year is over. .The next one- third will be spent by the West Bengal Government to look for the land. Then, they will get the plan sanctioned. The proposal will come up. Even if we give them ₹ 100 crores this year, they may barely spend ₹ 20 crores. Therefore, next year they may get ₹ 200 crores. It takes 3-4 years. So, this is only a start up amount which is mentioned against the scheme. It is not the total cost of a scheme. It is never so in a Government. You can start up a scheme by giving a token allocation of even one crore rupees. That is how the Government functions. During the UPA Government Budgets, year- after-year, schemes have been started in this manner. There is nothing wrong in it. The idea is, you put up the scheme and this becomes a road map of the scheme itself. We have not in a single case overlooked it. On the contrary, if you see the environment, one thing that has gladdened me was, this whole idea of horticulture, universities or IITs or IIMs or AIIMS, textile clusters, I can assure that in the course of our term, this year plus other years, depending on the resource availability, we are going to make sure each of these facilities is available to every State. We will be Centrally funding those schemes. If the growth rates move up, hopefully our flexibility in aiding those States will be more; instead of starting four AIIMS in a year, we can start eight AIIMS, if the spending capacity of the Central Government itself moves up. But the environment that it has created is, there is a healthy competitive feeling among the States. Each one of them is saying, "My State is also entitled to this because this is an asset my State needs." Well, this is a right competition to get into.

As far as Andhra and Telangana States are concerned, we have already announced some schemes. Under these schemes, we have promised some institutions to the two States. There was a promise by the previous Government. But every promise is going to be honoured. Whatever shortfalls are going to be there in the revenue, please be assured, from the budgetary support system, when the revised grants etc., come up, these promises are going to be honoured.

One last point, Sir, and I am not referring to others. There is a particular reason and method why I have given to individual taxpayers a large number of tax concessions. Inflation increases. Therefore, we need to strengthen that class in India which needs to have more spending power. Its spending power will also accelerate and move the market itself. I would have loved to do more, but I have raised the exemption limit from ₹ 2 lakhs to ₹ 2.5 lakhs. Never in the past Rs.50,000 exemption has been granted at one time.

[Shri Arun Jaitley]

It was ₹ 1.80 lakh during UPA, which became Rs. 2 lakhs. So, ₹ 20,000 was the maximum. In the first go, I have made it ₹ 50,000. For senior citizens, I have made it ₹ 3 lakhs. Since savings in India were down last year from 33 per cent to 30 per cent, I wanted individual taxpayers to start saving money. These savings eventually become investment. When you put money into PPF, insurance or banks, it becomes investment; it does not keep lying there. So, ₹ 1 lakh under Section 80C, I have increased it to ₹ 1.50 lakh. So every taxpayer can today save ₹ 50,000 more, and this ₹ 50,000 of saving will become investment for the country. To encourage real estate, to encourage people to buy their own houses, what I have done is this. If you buy a flat, you get a deduction of ₹ 2 lakhs every year. So, a deduction of ₹ 2 lakhs really means that you get ₹ 18,000 to ₹ 19,000 a month as a deduction for having bought a flat. If inflation moderates, and the Reserve Bank of India then considers it properly, which I am sure they will, to bring down the interest rates, we would like to go back to the situation which existed during Vajpayeeji's Government, that buying a flat becomes cheaper than taking it on rent. Your EMI is less than the rent that you are paying. So, if ₹ 18,000 is the tax rebate that you get for buying a flat, plus the interest rates are down, so that you can get loan from a bank or any other institution, that is how you will encourage the real estate activity in the country and the economy also will move up. All this is intended to give further incentives, as far as the market is concerned because this will all add in bringing the economy down. Our hope is, this year, from the sub 5 per cent growth, if we are able to move up, let us say, we move up one per cent plus or so in the first year, then we can start our onward journey to the strength to which the Indian economy eventually belonged to. In this particular process whatever points that I have made, I only urge the hon. Members on one fact that how much of it is a partisan issue and how much of it is a part of the national building exercise. We can have difference of policy, we can have difference of approach, we can have difference of ideas itself, but I would urge the hon. Members that these are areas on which the Government would be very keen to have the suggestions and also the support of each one of you. I am sure this difficult crisis that the Indian economy is going through in the last two years, will be able to overcome with the support of each one of you. There are one or two suggestions which I have made in the other House, as my colleague has said, with regard to wind energy and so on. The normal convention-is that whatever are the changes to the Finance Bill proposals, you do that at a time when the Finance Bill is taken. I will be making it in the course of tomorrow when the Finance Bill is taken up in the other House. With these words, I commend the Budget to the hon. House for acceptance.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, I want to put one question. He has talked about visa on arrival...

10.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. There is no time for such clarifications. I think it is enough. ...*(Interruptions)*... Okay, one clarification.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, after the Finance Minister having given a very comprehensive reply to the discussion which I had the privilege to start yesterday, I have just three short points to make. The rest we have said and that is a matter of record. There is no disagreement when it comes to infrastructure building and accelerating the process. For a developing economy, you are right, that infrastructure-choke points have to be removed.

But the fact is that this is an ongoing process and it has its own dynamics. What should also be acknowledged, which I expected of, is that this country has seen infrastructure expansion, when you go to our airports, be it Chennai, Bangalore, Hyderabad or anywhere, or, when you see our Metros, or when you see our power sector. Now, there is an issue on power and I agree with you because a developing economy needs energy, and all sources of energy need to be developed and accessed. But the fact is that despite all the challenges that you referred to, the power generation did go up from 1,12,000 MW to 2,40,000 MW...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sharma, please put your question. Just seek your clarification.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am just putting a point on record. The second is that inclusive growth remains a matter of concern and I must register this. I agree with you that wealth creation is an important part of economic activity and resource generation is an important part of economic activity. But it is equally important, in a country which is home to a very large number of poor people, for historical reasons, to lift them out of poverty, and for this, the growth has to be inclusive, development must be sustainable — that is important — and, equally, the wealth created must be reinvested, as has been said, as well as redistributed. That is what the social welfare concept is.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have a few clarifications. Yesterday I spoke about defence. I am happy that the Minister has elaborated it further. We both agree that it is a sensitive sector but an important sector. We have to reduce our dependence on imports and, therefore, the priority is to manufacture weapon systems in the country. But I did say that we also allowed more than 26 per cent. Mr. Minister, you are both the Defence Minister and the Finance Minister. You are privy to what was exchanged between the

[Shri Anand Sharma]

Ministry responsible for the FDI and the Defence Ministry. And, thereafter, a policy was put in place...

SHRI ARUN JAITLEY: The policy remains, exactly, the same. It is only that twenty-six per cent will be read as forty-nine per cent. That is all. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, let them have some patience. थोड़ा संयम भी रखिए। Sir, either we have a discussion which has gone very well or we have interruptions which is very unfair.

There are two points in what I am saying. One is about transfer of technology element which is a part of the policy, and I hope and I take that that will remain a part of the policy. Secondly, I hope that the Cabinet will have a role after the FIPB. Now whether it will go to the CCEA or the Cabinet Committee on Security, like we had, that is something which has not come out very clearly and that is what we would like to be reassured about. That is all on defence. Lastly,...

SHRI ARUN JAITLEY: The policy remains the same, as it was, except that 26 per cent will be read as 49 per cent. Everything else will remain the same.

SHRI ANAND SHARMA: The last thing which I have to mention is this. The Minister did say about our agreements and disagreements. Without revisiting any of them, -- they do happen and it is a part of history — I would mention one thing which is important. Since 1996, he referred to 1991, that is, opening up of the Indian economy, liberalisation and its positives — there have been areas where the Congress (I) did differ with the NDA Government when they opened up certain sectors. I will not go into those sectors or details...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No time for that.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Why dig up the past?

SHRI ANAND SHARMA: It is important that there was no policy reversal. Continuity of policies and stability of policies are important. Therefore, when they talk of taxation, the same applies to policies, their predictability and their stability, and that is why, there was no policy reversal. Even if we disagreed on insurance, we continued and expanded further.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all.

SHRI ANAND SHARMA: On multi-brand we had taken a view. I hope that the policy reversal message which will be a negative message will not go from your Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P. Rajeeve, you can put only a question, nothing more.

SHRI P. RAJEEVE: I will be very specific. The Finance Minister has not responded to the NPA. My query is regarding NPA. Is the Government ready to make any amendments to the existing legislation to control the Non-Performing Assets (NPA) of the banks? My second query is about revenue foregone. A different perspective is there, but what about the right of more than Rs. one lakh crore on the customs duty of gold and diamond. Are you rating it? ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Would you like to respond? ...*(Interruptions)*... No, no; that is all, Mr. Rajeeve. Please sit down.

SHRI P. RAJEEVE: Lastly, Sir, instead of disinvestment whether Government is ready to utilize the cash resources.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; Mr. Rajeeve, please sit down. Would you like to respond to this, Mr. Minister?

SHRI ARUN JAITLEY: No.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not responding. You please sit down.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I have one question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; you please sit down.

श्री भूपिंदर सिंह : सर, सिर्फ एक सवाल ...(**व्यवधान**)... मिनरल वाटर ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing you to speak. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री भूपिंदर सिंह : सर, मिनरल वाटर स्कीम कब से शुरू होगी ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing you. ...*(Interruptions)*... You listen to the Minister.

SHRI BHUPINDER SINGH: Why, Sir? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing you. You please sit down.

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, this is not proper. ...*(Interruptions)*.... This has never happened. Every Member of this House has an equal right. ...*(Interruptions)*... I can't put a question! Why are you not allowing me to do so?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen, listen.

SHRI BHUPINDER SINGH: I am sorry. ...*(Interruptions)*... This has never happened. I can't put a question? Why are you not allowing me? Why? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You sit down.

SHRI BHUPINDER SINGH: I thank you very much. I thank the hon. Finance Minister. क्या आप उसे इस फाइनेंशियल ईयर से लागू करेंगे? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not permitted you. This is not the way. You cannot speak without my permission. I have not permitted you.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, three small queries have been raised. The Budget Speech itself is very clear that mineral producing States will get the satisfaction that from this year we are going to revise the royalty rates and obviously you get those revised royalty rates. Odisha will be an important beneficiary. Jharkhand will be a beneficiary. One of the questions which were raised was that cooperative sector has been ignored. Paragraphs 89 and 90 of the Budget Speech elaborately deals with cooperative sector and the kind of assistance being given. Even though the UPA Government was in power and Mr. Sharma would be better equipped than me to answer it, I can simply tell you, this is like the tax foregone. A large number of gold and diamonds are imported into this country in large quantity. Value addition takes place and then they are re-exported back. Nobody writes off the customs duty because they come into this country only for value addition and then they go out. That notional duty structure is created only for that purpose.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up The Appropriation (No. 2) Bill, 2014 ...*(Interruptions)*.... I am not allowing anybody.

श्री राजीव शुक्ल : मंत्री जी, visa at arrival के बारे में बताएं?

श्री अरुण जेटली : Visa at arrival में कुछ कंट्रीज को एक्सक्लूड किया जाएगा। उसकी योजना बन रही है और 6 महीनों के अंदर 12-13 डिफाइंड एअरपोर्ट्स पर यह शुरू हो जाएगी। subject to exclusion of certain countries. Shuklaji, the infrastructure development will take time but we will start within the next six months.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : आपको पूरी दुनिया की चिंता हो गयी है? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please come back to the business. The Appropriation (No. 2) Bill, 2014 has already been moved. I shall now put the motion regarding consideration of The Appropriation (No. 2) Bill, 2014 to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the

financial year ended on the 31st March, 2012, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up the Appropriation (No. 3) Bill, 2014. The question is:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2014-15, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M.

The House then adjourned at twelve minutes past ten of the clock till eleven of the clock on Friday, the 25th July, 2014.